साफ्ट कोयले का उत्पादन व बिक्री

1577. **श्रीमती रेणुका चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों से साफ्ट कोयले के उत्पादन तथा बिक्री में कमी आई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऊर्जा विभाग के सलाहकार बोर्ड ने साफ्ट कोक के उत्पादन मे प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और इस पर मूल्य नियन्त्रण के हटाये जाने का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) पिछले कुछ वर्षों के दौरान साफ्ट कोक का उत्पादन और उठान इस प्रकार है :—

	1985–86	1986–87	1987–88 (अनतिम) (अप्रैल-सितम्बर)
उत्पादन	1.72 मि. टन	1.52 मि. टन	0.67 मि. टन
उठान	1.68 मि. टन	1.52 मि. टन	0.64 मि. टन

(ख) और (ग) ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड ने साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने पर एक अध्ययन किया है। ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड की सिफ रिशों में यह बातें शामिल हैं :—

(1) साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने के लिये नई तकनालाजी अपनाना ;

(2) गैर-सरकारी संगठनों को यह काम करने की अनुमति देना ;

(3) कीमत नियन्त्रण हटाना ;

(4) परिवहन लागत में कमी; और

(5) स्थानीय उपकरों मे कमी ।

इन सिफारिशों पर उपयुक्त फोरमों में विचार किया जायेगा और साफ्ट कोक के उत्पादन और उसे घरेलू ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की सम्भावना निर्धारित करते हुये नीति बनाई जाएगी ।

Assistance to the Rajasthan electricity Board

1578. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) The financial allocations made to the Rajasthan State Electricity Board with details of amount utilised during the last three years, year-wise;

(b) the Central assistance provided to the Rajasthan State Electricity Board during the last three years, year-wise; and

(c) to what extent the power generation was affected as a result of the non-utilisation of the funds allocated for the purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Oil wells in the country

1579. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) the State-wise break-up and location of oil wells in the country as on date;

(b) the amount and value of the gas being flared up per day since the commissioning of each well; and